

राजस्थान को नहीं मिला 3000 करोड़ का फंड:

राजस्थान में देर रात 26 आरपीएस के ट्रांसफर:

पुराने आदेशों के 5 तबादले रद्द, गृह विभाग ने जारी किए आदेश



भीम प्रज्ञा न्यूज

जयपुर । केंद्रीय वित्त आयोग ने राजस्थान को मिलने वाला करीब 3 हजार करोड़ का पिछले डेढ़ साल का फंड रोक रखा है। इस फंड का इस्तेमाल स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्र से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने में होता है। फंड रिलीज नहीं होने से गांवों में पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण जैसे कई विकास कार्य रुके हुए हैं। यहां तक कि करीब सवा लाख पंच और 11 हजार से ज्यादा सरपंचों को एक साल से मानदेय तक नहीं मिला है। मामला मुख्यमंत्री के स्तर पर पहुंचने के बाद पंचायती राज विभाग सक्रिय हुआ है। विभाग के सचिव जोगाराम ने वित्त आयोग को चिट्ठी लिखकर राज्य के हिस्से की राशि जारी करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, फंड रोकने की वजह पंचायत चुनाव समय पर नहीं करवाना है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की पहली किस्त वित्तीय वर्ष 2024-25 की जून-जुलाई में और दूसरी किस्त नवंबर में आनी थी। अभी तक यह राशि राज्य सरकार को नहीं मिली है।

पंचायत चुनाव में देरी का असर, कई प्रोजेक्ट अटके



क्या चुनाव नहीं करवा पाने के चलते रुका बजट?

विभागीय सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा फंड रोकें जाने के पीछे पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पाने को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग की स्पष्ट गाइड लाइंस है कि जो राज्य समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराते हैं, उन्हें वह फंड जारी नहीं करेगा। आयोग का यह मानना है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि ही ग्राम पंचायत की धुरी हैं। ऐसे में जब चुनाव ही नहीं हुए तो बजट क्यों जारी करें। यहां सवाल उठता है कि आखिर

राजस्थान में पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे? सरकार का कहना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निकायवार ओबीसी वर्ग के आंकड़े जुटाने हैं। आरक्षण तय होने के बाद वार्डों की लॉटरी निकालनी है। आयोग ने पहले सितंबर तक सर्वे पूरा करने का भरोसा दिया था, जिसके आधार पर दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित थे। सरकार का यह भी कहना है कि सूक्ष्म कार्यक्रम घोषित किए जाने के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

सवा लाख से ज्यादा पंच-सरपंचों का मानदेय रुका

जनवरी में ही हो गया था कार्यकाल खत्म

राजस्थान की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनमें से अधिकतर पंचायतों में सरकार ने मौजूदा सरपंचों को प्रशासक के रूप में कार्यरत रखने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में 1,09,228 पंच, 11,320 सरपंच जनता से चुने गए प्रतिनिधि हैं। सरकार ने इन्हें प्रशासक लगाया है, लेकिन एक साल से इन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है।

प्रदेश में करीब 7 हजार सरपंचों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी और मार्च में खत्म हो गया था। शेष ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर में खत्म हो गया था। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत सरपंच 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जानकारों का कहना है सरकार 6 महीने पहले सरपंचों को हटा सकती है, मगर चुनाव उसी समय करने चाहिए।

फंड नहीं मिलने से क्या नुकसान?

- सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई व्यवस्था नहीं
- नए बायो गैस एवं जैविक खाद प्लांट प्रबंधन कार्य धीमा
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बाधित
- सफाई कर्मियों के नए उपकरण खरीद पर रोक
- पार्कों और खेल मैदान की चारदीवारी और फुटपाथ निर्माण पर ब्रेक
- पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा बाधित
- पंचायती राज के अधीन विद्यालयों में कक्षा-कक्षाओं का निर्माण प्रभावित
- पेयजल टैंकों के निर्माण का कार्य धीमा हुआ
- पेयजल पाइप लाइन की स्थापना एवं रख-रखाव पर असर

इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर को हटाया: हॉस्पिटल पहुंचकर रोने लगे बच्चे और बड़े; CMHO ने कहा- शिकायतें मिल रही थी

भीम प्रज्ञा न्यूज

उदयपुर । उदयपुर के इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। वे बड़गांव सेटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी थे। चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। अशोक शर्मा को जयपुर मुख्यालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। एपीओ होने के बाद डॉक्टर अशोक शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 पोस्ट किए। पहले वीडियो में हॉस्पिटल से हटाने वाले आदेश का जिक्र करते हुए डॉक्टर ने कहा- मुझे क्यों और किस गलती से हटाया पता नहीं। वहीं, दूसरे वीडियो में शुक्रवार को वे उसी हॉस्पिटल में इलाज करते हुए मरीजों को बोल रहे हैं कि 'कुछ मरीजों का इलाज बाकी रह गया था, इसलिए आया हूँ। मेरा ऑर्डर आ गया है, अब जा रहा हूँ। मैं सोमवार तक यहां हूँ,'



इलाज करा लो।

रोने लगी बच्ची और उसकी मां

वहीं, दो अन्य वीडियो शुक्रवार शाम को करीब 4 बजे पोस्ट किए। इसमें डॉक्टर के लिफाफे के

कारण बच्ची और उसकी मां रो रही है। डॉक्टर उसे दिलासा देते दिख रहे हैं। बच्ची डॉक्टर को रोते हुए हाथ जोड़कर बोल रही है कि आप मत जाओ। इस पर वे खुद भी रोते हुए जवाब देते हैं कि मैं तुमसे जुड़ूँगा। छोड़कर नहीं जा रहा। वहीं, दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति तो रहा है। डॉक्टर अशोक शर्मा भावुक होकर उस मरीज से बोल रहे हैं कि हम आपसे जुड़ते हैं। ये उसका ही खेल है। पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। गरीबों का नुकसान हो जाएगा। मुझे जाने का दुख नहीं है। मेरी तनख्वाह तो वही है और बाद में प्रमोशन मिल जाएगा। बस ऐसे मरीज देखने को नहीं मिलेंगे। डॉक्टर ने कहा- नेता, एमएलए पावरफुल लोग हैं। हम कहीं और जगह बैठेंगे। नौकरी से इस्तीफा देंगे। ये अफसर हैं न, बड़े अधिकारी गुमराह करते हैं। नेताओं को तो पता भी नहीं पड़ता। मेरी आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोगों के लिए आया हूँ।

‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ अभियान के 6वें चरण का जिला स्तरीय वृहद कार्यक्रम सम्पन्न

भीम प्रज्ञा न्यूज.नीमराना।

रमेशचंद्र । कोटपुतली-बहरोड, 28 नवंबर - भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलाए जा रहे अन क्लेम फाइनेंशियल एसेट्स व जमाओं के निस्तारण एवं जागरूकता अभियान के तहत 6वें चरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम शुक्रवार को राजधानी टूरिस्ट मोटल कोटपुतली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। एलडीएम मोहन लाल मीणा ने बताया कि जिले के सभी बैंकों में लंबित 117532 खातों एवं लगभग 25.23 करोड़ रुपये की अन-क्लेम राशि में से आज आयोजित समारोह में 2472 लाभार्थियों को कुल 6.78 करोड़ रुपये के भुगतान के प्रमाण पत्र अतिथियों द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर से वीरेन्द्र चारण, एल.एल.बी.सी. प्रतिनिधि एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक बी.एल. मीना (उप महाप्रबंधक), पंजाब नेशनल बैंक के उप मंडल प्रमुख नरेश



गढ़वाल, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अजित खरविदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहन कूलदीप मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने अन-क्लेम खातों से राशि प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आरबीआई द्वारा प्रदान

की जा रही सुविधाओं के बारे में सरल भाषा में विस्तृत जानकारी दी। सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों ने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि वे वंचित लाभार्थियों की पहचान में बैंकर्स की मदद करें ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार वापस दिलाने में देरी न हो।

सिकन्दर राठौड़ बने स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, वार्ड न. 67 के अध्यक्ष

भीम प्रज्ञा न्यूज.बीकानेर।

सोहनलाल परिहार । स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ बीकानेर के शहर जिला अध्यक्ष हसन अली गौरी ने शुक्रवार को प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वार्ड नंबर 67 के अध्यक्ष के पद पर सिकन्दर राठौड़ को नियुक्त किया है। गौरी ने इस अवसर पर कहा कि राठौड़ की यह नियुक्ति न केवल संगठन की गतिशीलता को बढ़ाएगी, बल्कि वार्ड नंबर 67 में



प्रकोष्ठ की गतिविधियों और पहुंच को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिकन्दर राठौड़ अपने संगठनात्मक कौशल और जनसेवा के प्रति समर्पण से वार्ड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनकी नियुक्ति के बाद, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं और वार्ड निवासियों ने सिकन्दर राठौड़ को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत उपखंड अधिकारी सुमन सोनल ने बीएलओ को किया सम्मानित

भीम प्रज्ञा न्यूज.उदयपुरवाटी।

सुमेर मीणा । विधानसभा क्षेत्र के छापोली बुथ संख्या 193 के बीएलओ हेताराम जी गुर्जर के द्वारा किया गया बेहतरीन कार्य को देखते हुए उदयपुरवाटी उपखंड अधिकारी सुमन जी सोनल के द्वारा बीएलओ को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया इस सम्मानित से अन्य बीएलओ में भी जागरूकता पैदा हुई और उत्साहवर्धक हुए और साथ ही बीएलओ ने आम जन से अनुरोध किया है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में आम जन से भी सहायता मिल रही है लेकिन थोड़ी बहुत और जागरूक बनने की जरूरत है ताकि



आसानी से इस अभियान को सफल बना सकें इस अवसर पर नायब तहसीलदार गिरधारी लाल, पीओ छापोली विशाल गुप्ता, मास्टर ट्रेनर नरेंद्र जालोपिया, सुपरवाइजर कैलाश

चंद मीणा, गिरदावर भागीरथ मल, पटवारी कजोड मल मीणा,ग्राम सेवक पुष्प मल, सहित समस्त तकनीकी स्टाफ एवं सहयोगी स्टाफ आदि लोग मौजूद थे।

कबड्डी नेशनल खिलाड़ी हर्षवर्धन का खेलो इंडिया में चयन, बुहाना में खुशी की लहर

भीम प्रज्ञा न्यूज.बुहाना।

कस्बे के होनहार खिलाड़ी हर्षवर्धन पुत्र गिरवर सिंह का चयन खेलो इंडिया के पाँचवें संस्करण में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। हर्षवर्धन की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। खेलो इंडिया 2025 का आयोजन राजस्थान के विभिन्न शहरों-जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर-में हो रहा है। इसका मन्त्र्य उद्घाटन 24 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया।



प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डी.डी. स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है।हर्षवर्धन जेजेटी

युनिवर्सिटी, चुडुला (झुंझुनू) का छात्र है और राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में अपना लोहा मनवा चुका है। वह इससे पहले भी राजस्थान के लिए मेडल जीत चुका है, जिससे राज्य व क्षेत्र का मान बढ़ा है। उनके चयन की खबर मिलते ही परजनों ने मिठाई बाँटकर खुशी का इजहार किया। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, खेलप्रेमियों एवं ग्रामीणों ने हर्षवर्धन को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।हर्षवर्धन को इस उपलब्धि से न केवल बुहाना बल्कि पूरे जिले में गर्व की भावना है।

फुले को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न देना चाहिए : प्रदीप सैनी

भीम प्रज्ञा न्यूज.झुंझुनू।

अरुण कुमार । गुरुकुपा शिक्षण संस्थान में महिला शिक्षा के प्रेरणता महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पार्षद प्रदीप कुमार सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार को महात्मा ज्योतिबा फुले एवं इनकी धर्म पत्नी सावित्री बाई फुले को भारत रत्न देना चाहिए। 18वीं शताब्दी में महिला शिक्षा की अलग जगाना रात को सूरज की रोशनी पाने के समान था। वर्तमान में दिखाई दे रही शिक्षा के सूरज फुले दम्पति है। मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष इंद्राज सैनी कायस्थपुरा ने बताया कि फुले जैसे युग पुरुष दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। जो कमजोर और पिछड़े लोगों में सामाजिक बदलाव करवाते हैं। अध्यक्षता गुरुकुपा शिक्षण संस्थान के निदेशक राजेश कुमार सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि रामलाल सैनी, पेशनर समाज के जिला



मंत्री चन्द्र प्रकाश धूपिया, महावीर भारती थे। पुण्यतिथि कार्यक्रम में अनिल कुमार सैनी, पवन कुमार सैनी, रवि सैनी, इमरान, जतिन सैनी, विंदु शर्मा, संजु सैनी, पिकेश बोयल, नीलम सैनी, कोमल सैनी आदि उपस्थित रहे। संचालन संजय सिंगोदिया ने किया।



मित्र नहीं हो सकता चीन भारत को सावधान रहना होगा



मनोज कुमार अग्रवाल

अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न है और रहेगा। भारत उसकी हर घटिया हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में समर्थ है। उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं जितनी बढ़ेंगी, भारत की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, इसलिए अच्छा होगा कि वह अपनी घटिया हरकतों से बाज आए, ताकि रिश्तों में सुधार का जो सिलसिला चल रहा है, वह जारी रहे लेकिन चीन आदत से बाज आएगा इसमें संदेह की पर्याप्त गुंजाइश है।

अमेरिका के साथ व्यापार रिश्तों में कड़वाहट के बाद भारत का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है लेकिन चीन चीन एक बार फिर अपनी विस्तारवादी नीति, उकसावे की भाषा और ऐतिहासिक तथ्यों की मनमानी व्याख्या के सहारे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ गयी है। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय मूल की महिला पैमा यांगजोम घोंगडोक के साथ हुए व्यवहार पर भारत द्वारा दर्ज किए गए कड़े विरोध के बाद चीन की जो प्रतिक्रिया आई, वह न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मयादाओं का भी खुला उल्लंघन करती है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का यह कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, एक बार फिर यह साचित करता है कि बीजिंग ने तथ्यों, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक शालीनता से ऊपर अपनी साम्राज्यवादी सोच को रखा है। भारत को आपत्ति बिल्कुल वैध है, क्योंकि किसी भारतीय नागरिक को सिर्फ इसलिए इनवैलिड पासपोर्ट का हवाला देकर रोका जाए कि उसका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, यह चीन की मानसिकता को उजागर करने के लिए काफी है। पूरे मामले की शुरुआत पैमा वांगजोम के उस सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन ने उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बताकर रोका। केवल इसलिए कि जन्मस्थान की कॉलम में अरुणाचल प्रदेश, भारत लिखा था। यह घटना कोई तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि चीन की लंबे समय से अपनाई गई रणनीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल की भारतीय पहचान को चुनौती देने का प्रयास का एक और उदाहरण है। भारत ने सही ढंग से चीन को इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे बेतुका, अवैध और उत्पीड़क बताया। लेकिन जवाब में चीन ने न केवल अपनी गलती मानने से इंकार किया, बल्कि उल्टे अरुणाचल पर अपना दावा दोहराकर भारत को उकसाने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह बात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से निर्विवाद सत्य है। चीन द्वारा बार-बार उसके अस्तित्व को चुनौती देना केवल कूटनीतिक अशिष्टता नहीं, क्षेत्रीय अस्थिरता को भड़काने का प्रयास है। भारत का यह कहना बिल्कुल सही है कि एक यात्री को जन्मस्थान के आधार पर रोकना न सिर्फ बेतुका है बल्कि अंतरराष्ट्रीय विमानन व वीजा मानदंडों के खिलाफ भी है। चीन का यह रवैया बताता है कि उसकी



विस्तारवादी नीतियों अभी भी बरकरार हैं, चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो, ताइवान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। बार-बार ये बयान और ऐसे उत्पीड़क कदम इस बात का संकेत हैं कि बीजिंग वास्तविकता स्वीकारने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह कड़े व स्पष्ट कूटनीतिक रुख के साथ दुनिया के सामने चीन की मनमानी व आक्रामकता को उजागर करता रहे। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि सीमा विवाद से परे भी चीन की नीति में भारत विरोध की गहरी जड़ें हैं। दुनिया इसे समझ रही है और भारत को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रश्न पर किसी भी प्रकार का समझौता न करे। यह इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि चीन आए दिन अरुणाचल पर अपना दावा करता रहता है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है, वह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जांगनान कहता है और बार-बार दक्षिण तिब्बत का जिक्र करता है। चीन के मैप या मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। वो कभी-कभी इसका तथ्यांकित अरुणाचल प्रदेश के रूप में

उल्लेख करता है। चीन समय-समय पर भारतीय क्षेत्र पर अपने एकतरफा दावे को पुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को चीनी नाम देना देता रहा है। इसी साल मई महीने में अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का बेतुका काम किया था। विस्तारवादी चीन ने अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदले थे। चीन ने ये नाम चीनी यानी मंडेरिन भाषा में रखे थे। चीन ने इन जगहों की सूची ग्लोबल टाइम्स अखबार की वेबसाइट पर जारी की थी। चीन ने बीते आठ सालों में अरुणाचल प्रदेश की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। चीन द्वारा अरुणाचल के नाम बदलने पर भारत ने भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कहा था कि चीन का ये एक व्यर्थ और निरर्थक प्रयास है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। दरअसल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में मैकमोहन लाइन की कानूनी स्थिति को लेकर विवाद है। यह तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है, जिस पर 1914 के शिमला सम्मेलन में सहमति बनी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन में

चीन का प्रतिनिधित्व चीन गणराज्य के एक महादूत द्वारा किया गया था। उसे 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद महादूत घोषित किया गया था। वर्तमान साम्यवादी सरकार 1949 में ही सत्ता में आई थी। चीनी प्रतिनिधि ने शिमला कन्वेंशन पर सहमति नहीं जताते हुए कहा कि तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। शिमला में मुख्य ब्रिटिश वाताकार हेनरी मैकमोहन थे। उन्हीं के नाम पर मैकमोहन लाइन का नाम रखा गया। यह लाइन भूटान की पूर्वी सीमा से चीन-म्यांमार सीमा पर इस रज्जी दरें तक खींची गई थी। चीन मैकमोहन लाइन के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में स्थित त्वांग पर अपना दावा करता है। अपने दावों का आधार त्वांग और ल्हासा के मठों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी मानता है। चीन इसे एक तरह की दबाव की रणनीति के रूप में देखता है। यह बीजिंग की प्रोपेगंडा वाली विचारधारा का हिस्सा है, जिसके तहत जब भी कोई भारत का कोई सेलेब्रिटी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है, तो वह नाराजगी भरें बयान जारी करता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की संप्रभुता की मान्यता पूरी दुनिया में स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। विदेशी मीडिया में भी इस बात को लेकर कभी किसी तरह की कोई कंप्यूजन नहीं रही, लेकिन चीन तिब्बत के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करने की कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए सीमा विवादों के समाधान की कोशिश की है। पर चीन हर बार नाम बदलने, गलत दावे करने, मैप प्रकाशित करने और अब व्यक्तिगत नागरिकों को परेशान करने जैसी हरकतों से तनाव बढ़ाने की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन चीन को समझना होगा कि इस प्रकार की घटिया हरकत से उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न है और रहेगा। भारत उसकी हर घटिया हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में समर्थ है। उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं जितनी बढ़ेंगी, भारत की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, इसलिए अच्छा होगा कि वह अपनी घटिया हरकतों से बाज आए, ताकि रिश्तों में सुधार का जो सिलसिला चल रहा है, वह जारी रहे लेकिन चीन आदत से बाज आएगा इसमें संदेह की पर्याप्त गुंजाइश है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सम्पादकीय

एडवोकेट
हरेश पंवारContact No.
9983040937

मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है

सच का घूट कड़वा सही... पर यही ईसान और समाज को जिंदा रखता है?

आज के समय में सच बोलना और सच सुनना—दोनों ही दुर्लभ होते जा रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 'सच का घूट बहुत कड़वा होता है, अब तो बोलने और सुनने वाले दोनों ही कम रह गए।' यह पंक्ति केवल एक कथन नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरित्र का दर्पण है, जिसमें हमारी कमजोरियाँ, हमारी हिचक और हमारी बदलती संवेदनाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब समाज में सच बोलने वाले कम हो जाएँ और सच सुनने वाले उससे भी कम, तब समझ लीजिए कि कहीं न कहीं हमारे भीतर साहस और संवेदनशीलता दोनों क्षीण हो रहे हैं। यहाँ मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है।

सच बोलना आसान नहीं होता। सच अक्सर चुभता है, चोट देता है, और हमारे भीतर छिपे अहंकार, भ्रम और दिखावे की परतें उधेड़ कर रख देता है। यही कारण है कि लोग मीठे झूठ को सच की कटुता पर वरीयता देते हैं। झूठ भले क्षमति कर पर सुकून देता है, जबकि सच भले रास्ता दिखाए पर बचेहन भी करता है। आज परिवारों में, दफ्तरों में, राजनीति में, समाज में—हर जगह लोग सच से बचने की कोशिश करते दिखते हैं। क्योंकि सच सुनना आत्मावलोकन की मांग करता है और आत्मावलोकन का अर्थ है अपने दोषों से सामना करना। यह सामना असहज करने वाला होता है, इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि समाज की भी खड़ी विफलता है। जब समाज सच बोलने वालों को ताने, कटाक्ष या बहिष्कार देता है, तो धीरे-धीरे सच कहने वाले लोग मौन हो जाते हैं। एक सत्यवक्ता व्यक्ति बार-बार उपहास और विरोध झेलते हुए अंततः निराश हो जाता है और सोचने लगता है—'सच कहना किसके लिए और क्यों?' यह चुपौ समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जहाँ सच मर जाता है, वहाँ झूठ व्यवस्था बन जाता है। जहाँ लोग कड़वी सच्चाई से बचने लगते हैं, वहाँ सज्जद, दिखावा और भ्रम ही नीति का आधार बन जाते हैं। आज की पीढ़ी भी इस कड़वे सच का शिकार है। वे सच सुनना चाहती तो हैं, पर जब सच उनके आराधन या आदर्शों या सुविधा पर चोट करता है तो वे असहज हो उठते हैं। यही कारण है कि रिश्तों में संवाद टूटता जा रहा है, दोस्ती केवल दिखावे की रह गई है, और लोग सोशल मीडिया पर अपनी मनगढ़ंत छवि चमकाने में मशगूल हैं। सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण 'इमेज' बन गई है। हर कोई खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में उलझा है। सच सुनने का सामर्थ्य, आत्म सुधार की प्रवृत्ति और अपने दोषों की पहचान—ये सभी गुण क्षीण होते दिख रहे हैं।

लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है?

दरअसल सच सुनने के लिए जिस परिपक्वता, धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है, वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है। लोगों के भीतर संवेदनाएँ नाजुक हो गई हैं, आलोचना की क्षमता कमजोर हो गई है, और मन इतना नर्म पड़ गया है कि थोड़ी सी असहमति भी तुफान बन जाती है। लोग कम सहनशील हो गए हैं, जबकि सच सबसे पहले धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेता है। सच वही सुन सकता है, जिसके भीतर आत्मस्वीकृति की क्षमता हो, और सच वही बोल सकता है, जिसके भीतर निर्मलता और साहस हो। यही कारण है कि आज समाज में झूठ आसपास, चापलूसी और मीठी-मीठी बातें खूब विक रही हैं। कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि गलतियाँ उससे भी हो सकती हैं। परिणामस्वरूप लोग अपने-अपने भ्रमों में जी रहे हैं और धीरे-धीरे सत्य से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। यह रिश्ती अत्यंत चिंताजनक है। क्योंकि जहाँ सच नहीं होता वहाँ न्याय नहीं होता और जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ विश्वास टूट जाता है। समाज सत्य पर नहीं, विश्वास पर चलता है—और विश्वास केवल सच की जमीन पर ही पनप सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सच बोलने और सच सुनने की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। यह तभी संभव है जब हम स्वयं से शुरुआत करें। यदि हम सच बोलेंगे—बिना कटुता के, बिना लहंकार के और बिना चोट पहुँचाए—तो यह समाज के भीतर एक नई जागरूकता को जन्म देगा।



दिलीप कुमार पादक

फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतराष्ट्रीय एकजुटता दिवस, जो प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 181 के स्मरण में मनाया जाता है। यह फिलिस्तीनी अधिकारों और आत्मनिर्णय के लिए चल रहे संघर्ष को रेखांकित करता है, विशेष रूप से गाजा में मानवीय संकट के बीच। यह दिवस अंतराष्ट्रीय समर्थन, न्याय और फिलिस्तीनी राज्य के दर्जों को मान्यता देने का आ आ करता है। गाजा में पिछले वर्षों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, यह इलाका अपने इतिहास के सबसे गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और नाजुक युद्धविराम के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, यहाँ से आती हुई तस्वीरें देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का हृदय टूट जाता है, युद्धविराम लागू होने के बाद भी लगभग 67 बच्चों की मौत हो चुकी है ' गाजा में लाखों



डॉ. अंशुल उपाध्याय

आतंकवाद जाति और मजहब के नाम पर गहरा धब्बा है। जो लोग भी इस कृत्य में शामिल होते हैं उनकी जीवन प्रत्याशा अपने आप ही कम जाती है। एक ओर जहाँ आतंकी नेटवर्क को चलाने के लिए बालकों के दिमाग में जहर और तफरत भरकर उनको कम उम्र में ही इस काम में धकेल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रुपए और उनके परिवार का पोषण का जूटा वादा करके आतंकी बनने के लिए घसीट लिया जाता है।

अव्वल दर्ज की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग का नतीजा होते हैं आतंकी

बदलते परिवेश में मनोवैज्ञानिक तरीके से युवक और युवतियों का धीरे-धीरे ब्रेनवाश करके 15 से 16 वर्ष की आयु तक उन्हें एक ट्रेंड और क्रूर आतंकी बना दिया जाता है। फिर ये मासूम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसका खुद का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। और जो भी उन्हें आदेश या टारगेट दिए जाते हैं वे अपना दिमाग बिना चलाए आंख मूंद कर उन टारगेटों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। फिर चाहे उन्हें सुसाइड बंबर बनकर अपने ही शरीर के चौथड़े ही क्यों ना उड़ाने पड़े। आतंकवादियों को जरा भी इस बात का इन्त्य नहीं होता कि उन्होंने उनके इस काम से कितने मासूमों को मारा है।

इतनी क्रूरता आखिर किस लिए सिर्फ सरकार को दिखा देने के लिए या जनता को डराने के लिए? या फिर अपने नाकाम मानसून को पूरा करने के लिए? इस पर मैं बस इतना कहूँगी कि ये घटनाएँ सिर्फ एक क्रूर मनुष्य के दिमाग से जन्म लेती हैं और फैलिचित, ब्रेन लॉक मनुष्य के द्वारा अंजाम तक पहुँचाई जाती हैं।

लोग भीषण भूख और अकाल का सामना कर रहे हैं, और बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं ' 10 अक्टूबर 2025 को युद्धविराम समझौता हुआ, जिससे 20 बंधकों की सुरक्षित वापसी हो सकेगी तथा गाजा में सहायता बढ़ सकेगी। 13 अक्टूबर को, ICRC ने 20 बंधकों को इजराइली अधिकारियों और 1,808 फिलिस्तीनी बंदियों को गाजा और पॉ मी तट तक सुरक्षित पहुँचाया। उस दिन कुल 1,718 बंदियों और 250 कैदियों को रिहा किया गया, और ICRC ने सभी के रिहाई-पूर्व साक्षात्कार आयोजित किए। मृत बंधकों और फिलिस्तीनी बंदियों के अवशेषों का स्थानांतरण जारी है।

फिलिस्तीन के लिए यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 181 की याद में मनाया जाता है, जिसमें 1947 में फिलिस्तीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह दिवस 1978 से मनाया जा रहा है और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और अंतराष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों को उजागर करता है। इस वर्ष का स्मरणोत्सव, जो 29 नवंबर, 2025 को आयोजित होगा, गाजा में चल रहे मानवीय संकट के कारण एक अत्यंत मार्मिक समय पर हो रहा है, जो हाल के संघर्षों के कारण और भी बदतर हो गया है। फिलिस्तीनियों के लिए सम्मान, अधिकार, न्याय और

आत्मनिर्णय के मूल उद्देश्य पहले से कहीं अधिक मायावी प्रतीत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख ने हमस द्वारा किए गए हमलों और फिलिस्तीनियों को दी गई सामूहिक सजा, दोनों की निंदा की और तत्काल मानवीय राहत की माँग की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की ओर से सम्पूर्ण मानवीय सहायता की आवश्यकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुने गए, विशेष रूप से यूएनआरडब्ल्यूएस की ओर से, जो लाखों फिलिस्तीनियों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करती है। फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रयोग संबंधी समिति के अध्यक्ष शेख नियांग ने कहा कि पिछले दिनों में गाजा में 52,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इनमें आधे से ज्यादा महिलाएँ और बच्चे हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभूतपूर्व मानवीय आपदा थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने संप्रभु राज्यों की पारस्परिक मान्यता के साथ इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आ आ किया। अंतराष्ट्रीय दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और दुनिया भर के अन्य कार्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। इनमें विशेष बैठकें शामिल होंगी जहाँ वैश्विक नेता और कई देशों के प्रतिनिधि फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करेंगे और उनके अधिकारों को मान्यता देने का आग्रह करेंगे। पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी आज जॉर्डन, लेबनान, सीरिया,

गाजा पॉ और पॉ मी तट में रहने वाले लगभग 59 लाख पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करती है। UNRWA 663 से ज्यादा स्कूलों के माध्यम से शिक्षा, 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवा, और कमजोर आबादी के लिए खाद्य सहायता और नकद सहायता जैसी राहत सहायता प्रदान करती है। यह एजेंसी संघर्षों में आपात स्थितियों में आश्रय और आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करके भी प्रतिक्रिया देती है। यह अपने द्वारा संचालित 58 मान्यता प्राप्त शरणार्थी शिविरों में अपने बुनियादी ढाँचे में निरंतर सुधार कर रही है। लगभग 30,000 कर्मचारियों, जिनमें से स्वयं फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, के साथ यह अल्पकालिक मानवीय आवश्यकताओं और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, जैसे कि लाखों फिलिस्तीनियों को चल रहे संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने, दोनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह बेहद जरूरी है कि इस युद्धविराम समझौते का पालन किया जाए। हमें स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है, जिसमें सभी पक्ष गाजा में नागरिकों, सहायकारकर्मियों और चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिससे फिलिस्तीन में भी खुशियों की सुबह हो ' (लेखक पत्रकार हैं)

मासूम चेहरों के पीछे छिपा आतंकवाद, क्रूरता और विध्वंस



जिनका मकसद सिर्फ समाज में आतंकवाद डर को फैलाना होता है। **कश्मीर की आड़ में अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देते हैं आतंकी** आतंकवादी ऐसे लक्ष्य विहीन लोग होते हैं जो,कश्मीर की आड़ में कश्मीर को ही खोखला कर रहे है। कश्मीर में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने आतंक के इस डरावने चेहरे का सामान न किया हो। पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग अगर कश्मीर की आजादी की बात कर रहे है तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि जितना वह आतंक और नरसंहार फैला रहे है उसके बाद उनसे शांति और करुणा की बात करना बेफिजूल ही है। ये न केवल अपने खूनी मंसूबों को ही अंजाम दे रहे हैं। बल्कि हथियारों का निर्माण और उनकी तस्करी

करने वालों को भी सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। हथियारों की तस्करी करने वाले ये लोग तो अमीर देशों में बैठे हुए हैं। और आतंकवादी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हैं मिडिल क्लास और निम्न तबके के लोगों का। जबकि इन आतंकियों के जो हुक्मरान होते हैं वह खुद अपने बच्चों और परिवार को तो लाग्जरी लाइफ देते हैं और आम जन को बली चढ़ाने के लिए आतंकवाद की आग में झोंक देते हैं। **दिल्ली में विस्फोट के पीछे का काला सच** वर्तमान घटना क्रम की बात करे तो, दिल्ली लाल किले के पास हुए जोरदार कार धमाके में डॉ. उमर नबी ने करीब 30-40 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। पुलिस इस बात की आशंका जता रही हैं कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ने

विस्फोट को और खतरनाक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के अलावा दूसरे पदार्थों का भी इस्तेमाल भी किया होगा। जिसकी जांच अभी चल रही है। इन्हीं केमिकल पदार्थों के द्वारा ही धमाका काफी जोरदार हुआ था और इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी थी। मार्च 2020 में गिरफ्तार अलीपुर महिला सुधार गृह में बंद परखीन जो मौलाना मसूद अजहर की बहन, है और लश्कर - ए - तैयबा की एक हैंडलर भी है से पूछ ताछ में पता चला है कि वह खुद जेश की महिला शाखा की प्रमुख सईदा अजहर के निदेशों पर काम करती थी। परखीन कथित तौर पर आतंकवादियों के लिए ऑनलाइन भर्ती का काम संचालती थी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखती थी है। आज आतंकी सिर्फ पहाड़ों में छिपे बंदूकधारी नहीं रह गए है, बल्कि यहां तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और टेक-सेवी नौजवानों को भी आतंकी बनाया जा रहा हैं। भारत के भीतर व्हाइट कॉलर टेरर का ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है, जो मेडिकल पेशे की आड़ में देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा था। **घटना के बाद परिवार द्वारा शव का बहिष्कार** फि दायीन आतंकी डॉ. उमर नबी जिसके इस विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उसके शव के कई टुकड़े मोरारी में रखे हुए हैं। डीएनए से उसके शव की पहचान भी हो गई है। फिर भी उमर का शव लेने के लिए अभी किसी ने भी दावा नहीं किया है। ये वही डॉ. उमर है जो पहले विस्फोटक से लदी कार लेकर दिल्ली के वीआईपी इलाकों में घूमता रहा और बाद में इसने इस भयानक विस्फोट को अंजाम दिया। उमर की उम्र 43 वर्ष ही थी और वह अल फलहा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़ा हुआ था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही हैं। पर विचार करने वाली बात यही है की, ऐसे नौजवानों जो आतंक के हथ्ये चढ़ जाते है अपने पीछे अपने पूरे परिवार को जीवन भर के लिए बदनामी और सामाजिक बहिष्कार का हिस्सा बना जाते है। (लेखिका फॉर्मर यू.जी.सी. सीनियर रिसर्च फैलो (रक्षा एवं स्वातंत्रिक अध्ययन), दिल्ली रह चुकी हैं।)

टोहाना के गांव बोस्ती में ईश्वर बोस्ती गोदारा की बिटिया की शादी में विधायक बलवान सिंह आशीर्वाद देने पहुंचे

ईश्वर बोस्ती गोदारा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के नजदीकी रिश्तेदार हैं

भूमि प्रज्ञा न्यूज़.टोहाना।

रजत विजय रंगा । टोहाना उपमंडल के गांव बोस्ती में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल व टोहाना के पूर्व विधायक चौधरी हनुमान विश्‍नोई की बहन की पोती लक्ष्मी पुत्री ईश्वर बोस्ती की शादी में कई राजनैतिक हस्तिायों आशीर्वाद देने पहुंची। हरियाणा के कई राजनैतिक पार्टियों के नेता आशीर्वाद देने पहुंचे फतेहाबाद के कांग्रेसी विधायक बलवान सिंह व उनके बेटे, पूर्व विधायक चौधरी दूडा राम के भाई द्वारा प्रसाद एडनोकेट, प्रवीण पंजाब, विधायक के पुत्र भूपेंद्र पनहार, डीएसपी संजय विश्‍नोई, टोहाना के पूर्व

नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्षों ने रामेश्वर डूडी को अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

भूमि प्रज्ञा न्यूज़.बीकानेर।

सोहनलाल परिहार । राजस्थान के कदावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को उनके निधन के उपरांत श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में, बीकानेर देहात कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष बिशानाराम सियाग और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने आज डूडी जी के अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशानाराम सियाग ने स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए भावुकता से कहा, 'डूडी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही था, जिसके सहारे मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ।' उन्होंने डूडी जी के जनहितैषी विचारों को याद करते हुए उनके आदर्शों को दोहराया, 'डूडी जी हमेशा यह कहते थे कि हमारे हर प्रयास का लाभ आखिरी छोर के गौ-ढाणी तक के व्यक्ति को मिलना चाहिए।' सियाग ने आगे कहा कि वह



और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल मिलकर जनता के मुंहों को पूरी ताक़त से आवाज़ देंगे और डूडी जी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे।

श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख हस्तियां रही मौजूद

इस अवसर पर, श्रद्धांजलि देने वालों में कई प्रमुख स्थानीय नेता और जन

पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने उपाध्याय परिवार को दी नवीन गृह प्रवेश की शुभकामनाएँ



भूमि प्रज्ञा न्यूज़.बीकानेर।

सोहनलाल परिहार । बीकानेर में उपाध्याय लाखसर - गडसीसर रोड स्थित जैना महाराज के नवीन गृह प्रवेश समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सम्मिलित होकर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। गोविंद राम मेघवाल ने इस अवसर पर जैना महाराज जी उपाध्याय और उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके नए निवास के लिए मंगलकामना की। नवीन गृह में प्रवेश सदैव शुभ शुरुआत का प्रतीक होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह नया घर परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल लेकर आए।' उन्होंने परिवार द्वारा दिए गए स्नेह और सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कोलासर के चांद रतन रामाणी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी उपाध्याय परिवार को नवीन गृह प्रवेश की शुभकामनाएँ दीं। यह समारोह उपाध्याय परिवार के नए घर में प्रवेश का शुभ अवसर था, जिसे यादगार बनाने के लिए कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

छतरगढ़ पंचायत समिति के बाद विधायक मेघवाल का पहला दौरा: खाजूवाला में हुआ गर्मजोशी से स्वागत



भूमि प्रज्ञा न्यूज़.खाजूवाला।

छतरगढ़ को हाल ही में पंचायत समिति का दर्जा मिलने के बाद, क्षेत्र के विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल पहली बार 465 आरडी खाजूवाला पहुंचे। विधायक के इस महत्वपूर्ण आगमन पर, स्थानीय भाजपा के युवा नेता इंद्राज बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर, विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने 465 आरडी खाजूवाला में 'शहीद भगत सिंह बस स्टैंड' को शुरू करने के लिए स्थानीय भाग्यशाह सुरजा राम जी नदीवाल और समस्त व्यापारी गणों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस पहल को क्षेत्र के यात्रियों और आम जनता के लिए एक बड़ी सुविधा बताया। छतरगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा मिलने के बाद विधायक का यह दौरा क्षेत्र के विकास और आगामी योजनाओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गांव तिगरा का मनोज गांव में सार्वजनिक कार्य कर अपने परिवार परंपरा को आगे बढ़ा रहा है पूर्व सैनिक व आर्य समाज प्रधान ने अपने गांव में शमशान घाट का प्रवेश द्वार निर्माण व पौधारोपण किया, उद्घाटन 2 दिसंबर को

भूमि प्रज्ञा न्यूज़.मंडी अटेली।

मनोज बुलाण । एक सैनिक ने भारतीय सेना में अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के बाद रिटायर्ड के बाद गांव में समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्व सैनिक व आर्य समाज प्रधान मनोज कुमार ने अपने गांव तिगरा में अपनी दादी की याद में शमशान घाट प्रवेश द्वार निर्माण व उसमें पौधारोपण किया है। प्रवेश द्वारा का उद्घाटन 2 दिसंबर को रिटायर्ड कमांडेंट मोहर सिंह पुत्र स्व. रामजीलाल करेंगे। गांव निवासी धानेदार लाल सिंह, जगदीश ने बताया कि तिगरा निवासी सैनिक मनोज व आर्य समाजी ने अपनी दादी स्व. चंचा देवी की यादगार में शमशान घाट का प्रवेश द्वार बनवाया जिसका उद्घाटन 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इससे पहले उनके पूर्वजों ने भी अपनी कमाई का दान पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। उनके दादाजी रामजीलाल व झुथाराम ने अपने पिता तोखाराम की यादगार में परमार्थ में मोटर 1988 में लगवाई और टंकी बनवाई। मनोज के ताऊ



भौड़ी के किसान के खेत में डेढ़ एकड़ की रखी कड़बी को अज्ञात लोगों ने को जलाया, कड़बी जलकर हुई राख

भूमि प्रज्ञा न्यूज़.मंडी अटेली।

मनोज बुलाण । गांव भौड़ी निवासी किसान के खेत में डेढ़ एकड़ की रखी कड़बी को अज्ञात लोगों ने बृहस्पतिवार रात्रि को जलाकर राख कर दिया। जली कड़बी के पास ज्वलनशील पदार्थ बिखरा हुआ है, जो कड़बी को इरादे से जलाने की बू आ रही है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी मौके पर पहुंच कर मशकत से आग पर काबू पाया लेकिन उस समय तो कड़बी जल कर राख हो चुकी थी।



उस कड़बी के छोर से थोड़ी दूर एक अन्य किसान कड़बी की बागर लगी हुई थी। गांव के पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह के पुत्र बिनोद ने बताया कि मदन सिंह किसान पौड़ित गरीब है, अपनी डेढ़ एकड़ में खेती परिवार चलता है। रात्रि को किसान

एक विवाह समारोह में गया हुआ था। आग की सूचना पड़ोसियों ने फोन पर दी। जिला उपायुक्त से आर्थिक सहायता की गुहार लगायी है। इसकी सूचना अटेली थाने में भी दी है। आग के कारणों का मालूम अभी तक नहीं चला है।

परिसीमन विवाद गहराया: 4 बीएमआर के ग्रामीणों का प्रदर्शन, दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी



भूमि प्रज्ञा न्यूज़.बज्जू/बीकानेर।

सोहनलाल परिहार । बज्जू उपखंड के चक 4 बीएमआर ग्राम के निवासियों ने ग्राम पंचायत के हालिया परिसीमन पर गंभीर विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को बज्जू उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मुख्य आपत्ति यह है कि परिसीमन प्रक्रिया के तहत उनके गांव को लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित भूरासर ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया गया है। ग्रामीणों का तर्क है कि उनका गांव भौगोलिक और सामाजिक रूप से बरसलपुर पंचायत के अधिक निकट है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 20 किलोमीटर दूर नई पंचायत में शामिल होने के कारण उन्हें मूलभूत प्रशासनिक, सामुदायिक और दैनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें भारी असुविधा होगी।

आपत्तियाँ अनसुनी, सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी

ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया के दौरान कई बार लिखित में आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनके गांव चक 4 बीएमआर को तत्काल बरसलपुर ग्राम पंचायत में वापस शामिल नहीं किया जाता है, तो वे सभी आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं और चुनावों का सामूहिक बहिष्कार करेंगे।

विरोध प्रदर्शन में इनकी रही उपस्थिति

यह विरोध प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता श्री कैलाश चंदेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान दीपाराम चंदेल, पुरखाराम, गोमाराम पन्नु, नरेश चंदेल, कर्णेश चंदेल, लालू राम प्रजापत, पोकर राम सेंजू, किशोर कुमार, खेताराम और अन्य ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों के ज्ञापन को स्वीकार करते हुए उनकी मांग को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

परिसीमन के विरोध में काकड़ा पंचायत के ग्रामीणों का प्रदर्शन पुनः नोखा पंचायत समिति में शामिल करने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

भूमि प्रज्ञा न्यूज़.नोखा/बीकानेर।

सोहनलाल परिहार । नोखा उपखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ हाल ही में हुए प्रशासनिक पुनर्विन्‍यास का स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। काकड़ा ग्राम पंचायत के निवासियों ने काकड़ा पंचायत में शामिल करने की मांग की। जसरासर में शामिल करने पर विरोध ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद काकड़ा पंचायत को जसरासर



पंचायत समिति में जोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का तर्क है कि इस बदलाव से क्षेत्र की जनसुविधाओं, विकास कार्यों और दैनिक प्रशासनिक कार्यों पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार, काकड़ा पंचायत की सामाजिक, भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति नोखा पंचायत समिति के साथ अधिक मेल खाती है। इसलिए, इसे दूर स्थित जसरासर पंचायत समिति में जोड़ना न्यायसंगत नहीं है।

ज्ञापन देने वालों में प्रमुख लोग शामिल

इसी मूदे पर पुनर्विचार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में

युवा और बुजुर्ग ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से श्री भगवान सरपंच, श्री रामप्रताप पटवारी (पूर्व प्रधान प्रतिनिधि), श्री इमिलाल जी जाणी (कोऑपरेटिव सोसायटी अध्यक्ष), बनवारीलाल डेलू, रतनलाल भरताणी, मांगीलाल विश्‍नोई, दामोदर पारीक, महेंद्रराम डेलू, रामकिशन मेघवाल, शंकरलाल मेघवाल, गंगाजल विश्‍नोई, मुनीराम विश्‍नोई, श्रीराम डेलू, बगड़ावतराम पुनिया और गोरधन विश्‍नोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लेने और काकड़ा पंचायत को पुनः नोखा पंचायत समिति का हिस्सा बनाने की पुर्जोर मांग की है।



महिला-प्रधान फिल्म होगी कल्याणी प्रियदर्शन की अगली फिल्म

तमिल अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म लोका ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और उन्हें पैन-इंडिया स्टार के रूप में मजबूती भी दी। इस सफलता के बाद दर्शक और फैस अब उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इस कड़ी में उनकी नई फिल्म की आधिकारिक जानकारी सामने आई है, जो उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल्याणी प्रियदर्शन की अगली फिल्म की खास बात यह है कि यह महिला-प्रधान कहानी है। फिल्म की पूरी कहानी एक महिला पात्र के इर्द-गिर्द घूमेगी और उसकी भावनाओं, संघर्षों और सफर को मुख्य रूप से दिखाया जाएगा। अभिनेत्री ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म का निर्देशन थिरियम एस. एन. कर रहे हैं, जो इस फिल्म के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वहीं, फिल्म का निर्माण पोटेंशियल स्टूडियोज कर रहा है। यह फिल्म उनका सातवां प्रोजेक्ट है और इससे पहले वे माया, मानगरम, मॉन्टर, तानकरन, इरुगापत्रु और ब्लैक जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। इन सफल फिल्मों के चलते दर्शकों का विश्वास इस बैनर पर पहले से ही बना हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि उनकी यह नई फिल्म भी उसी गुणवत्ता को आगे बढ़ाएगी। कल्याणी प्रियदर्शन की कामयाबी और पोटेंशियल स्टूडियोज की लगातार सफल फिल्मों की सीरीज ने इस नए प्रोजेक्ट को पहले ही एक बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है। दर्शक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि कल्याणी इस बार किस तरह का किरदार निभाएंगी। फिल्म में कल्याणी के साथ देवदर्शिनी और नान महान अल्ला फेम विनोद किशन भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग चेन्नई में शुरू हो चुकी है। फिल्म के डायलॉग्स प्रवीण भास्कर, श्री कुमार और खुद निर्देशक थिरियम ने मिलकर लिखे हैं। संगीत की कमान तमिल फिल्म जगत के उभरते हुए संगीतकार जस्टिन प्रभाकरन ने संभाली है, जिनकी धुनें हमेशा दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं।



सोनाली बेंद्रे का फिल्मी करियर

सोनाली बेंद्रे का कहना है, मैं हमेशा अपनी यात्रा ईमानदारी और विनम्रता के साथ शेर करूंगी। कभी किसी नुस्खे के तौर पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव के तौर पर। बता दें कि सोनाली मेटास्टैटिक कैंसर के खिलाफ जंग लड़ चुकी हैं। अभिनेत्री के करियर की बात करें तो उन्होंने आग (1994) से डेब्यू किया था। वे सरफरोश (1999), हम साथ-साथ हैं (1999), हमारा दिल आपके पास है (2000), लज्जा (2001) और कल हो ना हो (2003) जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

नैचुरोपैथी का समर्थन करने के बाद हुई ट्रोलिंग पर सोनाली बेंद्रे ने तोड़ी चुप्पी

सोनाली बेंद्रे कैंसर सर्वाइवर हैं। उन्होंने 2018 में इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कैंसर से जंग में नेचुरोपैथ भी उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। इसके बाद वे मेडिकल प्रोफेशनल्स के निशाने पर आ गईं। डॉक्टर साइरिक एबी फिलिप्स ने उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोनाली की पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि, आपका कैंसर कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से ठीक हुआ, ना कि नेचुरोपैथी से। आलोचनाओं और सवाल के बाद सोनाली बेंद्रे ने चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेर किया है।

सोनाली ने नेचुरोपैथी को लेकर क्या कहा था?

सोनाली बेंद्रे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए एक पोस्ट में लिखा था, साल 2018 में जब मुझे कैंसर का पता चला तो मेरे नेचुरोपैथ ने मुझे ऑटोफेगी नाम की एक स्टडी के बारे में बताया। इसने मेरी रिकवरी में बहुत बढ़ी

भूमिका निभाई, इसलिए मैंने इसे पढ़ा, सीखा, प्रयोग किया और धीरे-धीरे इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया। मैं तब से इसे फॉलो कर रही हूँ। सोनाली के इस सवाल पर डॉक्टरस ने सवाल उठा दिए। डॉक्टर साइरिक एबी फिलिप्स ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेर कर दिया। बता दें कि डॉक्टर साइरिक एबी फिलिप्स भारतीय हेपेटोलॉजिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर द लिवर डॉक के नाम से जाने जाते हैं।

विरोध के बाद सोनाली ने तोड़ी चुप्पी

विरोध के बाद सोनाली ने अब एक अन्य पोस्ट शेर किया है। इसमें उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है, हम सभी का सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें एक-दूसरे को सिर्फ इसलिए खारिज करने से बचना चाहिए क्योंकि हम अलग-अलग तरीकों की तरफ झुकते हैं। सोनाली लिखती हैं, मैंने कभी डॉक्टर होने का दावा नहीं किया, लेकिन मैं पक्का कोई नीम-हकीम भी नहीं हूँ। मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, जिसने इस बीमारी से होने वाले डर, दर्द, अनिश्चितता और फिर से बनने की प्रक्रिया को झेला है।



शाहरुख की फिल्म 'किंग' में अक्षय ओबेरॉय की हुई एंट्री

शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग की एक-एक अपडेट का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अब फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी आ रही है कि इस फिल्म में एक और कलाकार का नाम जुड़ गया है। जानिए उस अभिनेता के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'किंग' का हिस्सा हैं। आपको बताते चलें कि कई दिनों से चर्चा चल रही थी, अभिनेता इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। हालांकि अब इसपर मुहर लगती दिख रही है। फिल्म किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े नाम भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त तक खलनायक के रूप में नजर आए ये बड़े स्टार्स

बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं ने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है। अपकॉमिंग फिल्म धुरंधर में अर्जुन रामपाल खलनायक के किरदार में नजर आने वाले हैं। इससे पहले भी कई अभिनेताओं ने फिल्मों में पारंपरिक खलनायक से अलग लुक रखा और अभिनय किया। दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया। कई विलेन ऐसे रहे जो नायकों पर भारी पड़े और उनकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली।



फिल्म सिंघम अगेन (2024) में अर्जुन कपूर ने डेंजर लंका का नेगेटिव किरदार निभाया है। उनका किरदार एक चालाक और तेज दिमाग वाला है। फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और कई कलाकारों ने अभिनय किया लेकिन अर्जुन कपूर के किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म शेतान (2024) में



रिलीज हुई फिल्म एनिमल को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसमें रणबीर कपूर के किरदार के अलावा बांकी देओल के नेगेटिव किरदार अबरार अहमद को पसंद किया गया। फिल्म में उनके कम संवाद, चमकीली आंखें और शांत गुस्से ने दर्शकों को हैरान कर दिया था। विलेन के रूप में बांकी देओल को दर्शकों ने पसंद किया। फिल्म पद्मावत (2018) में रणवीर सिंह ने विलेन अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया। इस फिल्म में नायक से ज्यादा खलनायक को दमदार दिखाया गया। अलाउद्दीन खिलजी का किरदार बेरहम, जुनूनी और

आर माधवन ने वनराज कश्यप का नेगेटिव किरदार निभाया। यह फिल्म गुजराती फिल्म वश पर आधारित थी। इसमें दिखाया गया है कि एक अजनबी एक लड़की को वश में करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है। इसमें आर माधवन के किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। साल 2023 में

डरावना था। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म अनिपथ में संजय दत्त ने विलेन का किरदार निभाया। कानों में कुड़ल और बिना बालों के संजय दत्त के लुक को काफी पसंद किया गया। फिल्म में वह इग डीलर बने हैं। त्रैतिक रोशन के अपोजिट संजय दत्त ने एक डरावना लेकिन आकर्षक अभिनय किया।



भगवान शिव का किरदार निभाने को लेकर बोले मोहित मलिक

मोहित मलिक ने डोली अरमानों की और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे टीवी शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाई। वह दो दशक से भी ज्यादा समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दर्जनों टीवी शो और वेब सीरीज कर चुके मोहित मलिक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस वक्त वह माइथोलॉजिकल शो महागाथा शिव परिवार की - गणेश कालिकेय में काम कर रहे हैं, जिसमें वह भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं। मोहित मलिक ने अपने इस किरदार के अलावा 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस पर बात की।

मोहित मलिक पहली बार माइथोलॉजिकल शो में काम कर रहे हैं। वह गाथा शिव परिवार की-गणेश कालिकेय में भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। इस शो में काम करने की वजह पर वह कहते हैं, इस शो मेकर्स का नजरिया अलग था। उन्होंने मुझे कवीस किया कि वह इसका प्रेजेंटेशन वैसे ही करेंगे जैसा उन्होंने मुझे बताया है। फिर इसमें शिव का रूप भी एकदम अलग है।

वह उस तरह का टिपिकल नहीं है जैसा लोग अब तक देखते आए हैं। शिव और उनके परिवार को इंसानी रूप में दिखाया गया है। बर्काल मोहित, शिव के आशुतोष रूप का प्रभाव मेरे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है क्योंकि वह बहुत भोला है, दयालु है और सबको जल्दी से माफ कर देते हैं। मैं उनसे सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ।

AI का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कैसा रहेगा प्रभाव?

मोहित ने इस दौरान मनोरंजन जगत में AI पर भी बात की। जब हमने पूछा कि AI एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह प्रभावित करेगा? तो मोहित ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि कभी पूरी तरह AI से फिल्में और शोज बनेंगे। हालांकि यह बहुत अच्छी तकनीक है लेकिन उसे एक सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी AI बेस्ड महाभारत देखूंगा क्योंकि मुझे असली परफॉर्मेंस, असली लोग, असली इमोशंस चाहिए। ऑडियंस भी एक्टर से कनेक्ट होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी पूरे AI बेस्ड शो बनेंगे।

पैसे को लेकर आपका पहला सबक क्या है?

मेरी जिंदगी में पैसा कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैं हमेशा से अच्छा काम करना चाहता था। बस इतना था

कि मैं अपना घर खरीद लूँ और गाड़ी ले लूँ। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा बर्लेस होना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास परिवार है। जैसे पहले मैं रोल को तवज्जो देता था और सोचता था कि उसके लिए पैसों से समझौता कर लूंगा। लेकिन अब मैं पैसों को लेकर समझौता नहीं करता। अब मैं तो डिजिटल करता हूँ, वह मांगता हूँ और वह मिल भी रहा है।

8 घंटे नहीं 12 घंटे की

वर्किंग शिफ्ट ठीक

मोहित मलिक ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर कहा, हमारे यहां आमतौर पर 12 घंटे की शिफ्ट होती है और मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि बस आठ घंटे की वर्क शिफ्ट होनी चाहिए, तो यार आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में भी तो सोचो। एक एक्टर सेट पर आता है, फिर एक घंटा वह मेकअप करता है। तो आठ घंटे में कितना ही काम होगा। मुझे 12 घंटे ठीक लगते हैं। मैं उससे ज्यादा शूटिंग नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि शूटिंग के घंटे 14 नहीं होने चाहिए। 14 घंटे आप बतौर एक्टर काम कर भी नहीं सकते। 12 घंटे से ज्यादा काम करना आसान नहीं होता। मगर आठ घंटे से प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होगा।

आपकी पहली कमाई क्या थी?

मेरी पहली कमाई दिल्ली में थी और उससे मैंने कुछ खरीदा नहीं था। मैंने अपनी दादीजी को जाकर चेक दे दिया था। उसके बाद तो मैंने शुरू में कपड़े खरीदना और जो लड़कों के शौक होते हैं, वह पूरे किए थे।

आपका सेविंग मंत्र क्या है?

सेविंग मंत्र है कि लगभग 30-40 फीसदी कमाई में से बचाना होता है। जाहिर है कि सेविंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिस एक्टिंग की इंडस्ट्री में हैं, वह बहुत ही अनिश्चित है। हालांकि हम देखते हैं कि हमारा मासिक खर्च कितना है और हम कितना बचा सकते हैं। आपने अब तक सबसे महंगा खर्च क्या किया है? सबसे महंगा तो मैंने अपना घर ही लिया है मुंबई में।

आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है?

मैंने उसे लेकर कोई प्लान नहीं बनाया है। इसलिए चाहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ, एक्टिंग करता रहूँ। आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? पैसों की सेविंग बहुत जरूरी है। और उसी के साथ जिंदगी एंजॉय करनी भी जरूरी है। सिर्फ सेविंग के चक्कर में आज की जिंदगी मत गंवाओ। तो जितना कमा रहे हो, उसमें से थोड़ा एंजॉय करने के लिए खर्च करो। मगर पूरा मत खर्च करो। थोड़ा सेविंग भी करो।



संक्षिप्तसमाचार

दिल्ली में सुबह-सुबह एनकाउंटर, भाऊ गैंग के बड़े बदमाश ने खाई गोली

नई दिल्ली, एजेंसी। झारका जिला पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल लंबे समय से फरार चल रहे हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर को गुरुवार सुबह एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। आरोपी 25 वर्षीय अंकित पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। दिल्ली पुलिस के अलावा उसे हरियाणा पुलिस भी लंबे समय से तलाश रही थी। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर को नजफगढ़ इलाके में हुई गैंगवार के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के शूटरों ने रोहित लांबा पर फायरिंग की गई थी। रोहित इस फायरिंग में बच गया था। पुलिस ने दोनों ने उसके बचान पर केस दर्ज कर जांच शुरू की और कार आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन मामले में शामिल दोनों शूटर अंकित और दीपक फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि शूटर अंकित नजफगढ़ स्थित साई बाबा मंदिर के पास आने वाला है। पुलिस ने यूसुआर-2 के पास ट्रैप लगाया और अंकित का इंजकार शुरू किया। सुबह करीब 8.05 बजे अंकित बाइक से वहां पहुंचा। अंकित को देखकर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने बाइक से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की एक गोली हेडकांस्टेबल कुलदीप को लगी। लेकिन बुलेट फ्लूक जैकेट पहने होने के चलते वह बच गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें अंकित के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अंकित को पकड़ लिया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने उपचार के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 2020 में पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने के आरोप में लंबे समय से हरियाणा पुलिस भी तलाश कर रही थी।

बढ़ गई रोशनआरा क्लब की मेंबरशिप पाने की तारीख



नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आपने अभी तक दिल्ली के रोशनआरा क्लब की सदस्यता नहीं ली है, तो ये खबर आपके लिए है। डीडीए ने रोशनआरा क्लब की लाइफटाइम सदस्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। सारे आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकारे जाएंगे। सरकारी कैटेगरी की 350 और गैर सरकारी कोटे की 400 सीटें होंगी। यदि आवेदनों की संख्या सीटों की संख्या से अधिक होती है, तो चयन कंप्यूटरीकृत ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। रोशआरा की सदस्यता के लिए आवेदन शुल्क भी तय है। आवेदक को भारतीय नागरिक होने के साथ उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और अप्लीकेशन की रकम 2500 रुपये है। इसके अलावा गैर सरकारी लोगों के लिए मेंबरशिप शुल्क 12.5 लाख और सरकारी लोगों के लिए 4 लाख रुपये है। इसमें जीएसटी की रकम अलग से जोड़ी जाएगी। डीडीए अधिकारी ने कहा, यह विस्तर उन इच्छुक सदस्यों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से है जो व्यक्तिगत या लॉजिस्टिक्स कारणों से पहले अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। साथ ही यह ऐतिहासिक खेल और सामाजिक संस्थान तक व्यापक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करेगा। यूरोपीय शैली के दरवाजा और खिड़कियां, मैंगलोर टाइल वाली छत और जटिल लकड़ी के टूस शामिल हैं।

ऐसा क्या आदेश दें कि तुरंत साफ हो जाए हवा जादू की छड़ी नहीं; दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों के आते ही हवा का हाल ऐसा हो जाता है मानो पूरा इलाका जहरीली धुंध के घेरे में कैद हो जाता हो। इस गंभीर समस्या पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कदम उठाने का संकेत दिया है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता से जुड़ी एक याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संकट को लगातार निगरानी की जरूरत है।सीजेआई सूर्य कांत और जस्टिस ज्योमलया बागची की बेंच ने वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में सख्यता दे रही वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलीलों पर विचार किया। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे हेल्थ इमरजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए। सीजेआई ने इस संकट की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा, अदालत के पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह स्थिति दिल्ली-एनसीआर के लिए कितनी खतरनाक है। समस्या यह है कि इसके कारणों और समाधानों की पहचान करनी होगी। समाधान तो क्षेत्र के विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दीर्घकालिक उपाय ढूंढना आवश्यक है। सीजेआई कांत ने कहा, मुझे बताएं कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं कि हम कुछ निर्देश दे सकें और तुरंत साफ हवा मिल सके। हम सभी जानते हैं कि समस्या क्या है। हमें सभी कारणों की पहचान करने की जरूरत है। कोई एक कारण नहीं है। ऐसा सोचना एक बड़ी गलती हो सकती है। केवल



डोमेन एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ही इस पर गौर कर सकते हैं। फिर हमें देखना होगा कि हर क्षेत्र में क्या समाधान हो सकते हैं। आइए देखें कि सरकार ने कमेटी के तौर पर क्या बनाया है।

तात्कालिकनिर्देशों से आगे बढ़नेकी जरूरत

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कुछ अस्थायी निर्देश जारी करने से हवा तुरंत शुद्ध नहीं हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग समाधानों पर विचार करना होगा और इसके लिए सरकार द्वारा गठित समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को केवल दिवाली के मौसम तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे नियमित रूप से निगरानी में रखा जाए।



इससे पहले 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएनयूएम) को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर के दौरान निर्धारित खुले खेल आयोजनों को अधिक सुरक्षित महीनों में स्थगित करने पर विचार करें। अदालत ने ग्रेप के तहत साल भर सख्त पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का मानना ​​है कि आपातकालीन उपायों के बजाय लंबे समय तक चलने वाले और टिकाऊ समाधानों पर ध्यान देना जरूरी है। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने जहरीली हवा के इस जटिल संकट को केवल मौसमी समस्या के रूप में न देखते हुए निरंतर निगरानी और एक्सपर्ट के सहयोग से स्थायी समाधानों की दिशा में कदम बढ़ाने पर बल दिया है। 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में इस दिशा में आगे की रणनीति पर विचार होने की उम्मीद है।

इस्राइल ने लौटाए 15 और फलस्तीनियों के शव सीजफायर के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए मिले तीन देशों के अधिकारी



तेल अवीव, एजेंसी।

इस्राइल ने पंद्रह और फलस्तीनियों के शव सौंप दिए हैं। संघर्षविराम समझौते का पहला चरण खत्म होने के करीब है और अधिकारी दूसरे चरण पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। गाजा में अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उस समय हुआ है, जब फलस्तीनी लड़ाकों ने इस्राइली बंधक झोर ओर के अवशेष लौटाए हैं। इस्राइली सेना का कहना है कि हमास के सात अक्तूबर 2023 के हमले में उनकी मौत हो गई थी। समझौते के तहत इस्राइल हर एक बंधक के बदले 15 फलस्तीनी शव लौटाने के लिए तैयार हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ताजा आदान-प्रदान के बाद इस्राइल अब तक कुल 345 फलस्तीनी शव

गाजा वापस भेज चुका है। ये आदान-प्रदान पिछले महीने शुरू हुए थे। गाजा में अभी भी दो लोग हमास की कैद में हैं। इनमें एक इस्राइली और एक थाई नागरिक है। तुर्किये, कतर और मिस्र के अधिकारियों ने बुधवार को काहिरा में मुलाकात की, ताकि संघर्षविराम के दूसरे चरण पर बात की जा सके। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर संघर्षविराम के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यह संघर्षविराम अब तक बना हुआ है। समझौते के अगले चरणों में एक अंतरराष्ट्रीय बल को तैनात करना और गाजा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक ढांचा बनाना शामिल है, जो पुनर्निर्माण कार्य की निगरानी भी करेगा। सशस्त्र अंतरराष्ट्रीय स्थिरकरण बल का काम सुरक्षा बनाए रखना और हमास का

निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना होगा। यह इस्राइल की मुख्य मांग है। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि वे इस बल के लिए 20 हजार शांति सैनिक भेजने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के लगभग हर हिस्से और इसे लागू करने के समय को लेकर सवाल बने हुए हैं। इस बीच, लगभग सभी फलस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हैं और मानवीय मदद पर निर्भर हैं। हमास अभी भी गाजा के लगभग आधे हिस्से पर बड़ा नियंत्रण रखता है और गाजा के पुनर्निर्माण की शुरुआत भी मुश्किल से हुई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस्राइल की ओर से लौटाए गए 345 शवों में से केवल 99 की पहचान हो सकी है। उनका कहना है कि गाजा में डीएनए परीक्षण किट की कमी के कारण पहचान की प्रक्रिया बेहद मुश्किल है।

पहले मौत की सजा, अब भ्रष्टाचार मामले में 21 साल की जेल

ढाका, एजेंसी।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कोर्ट ने पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल जेल की सजा सुनाई है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले आईसीटी ने उन्हें मौत की सजा सुना चुका है।

दरअसल, ढाका के स्पेशल जज 5 मोहम्मद अब्दुल्ल मलमून ने शेख हसीना को तीन प्लॉट फ्रॉड केस में 7-7 साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि बांग्लादेश के एंटी-करण कमीशन ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुरवाचल इलाके में कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से सरकार प्लॉट बांटने के लिए छह अलग-अलग मामला दर्ज कराए थे। बाकी तीन मामलों में फैसला 1 दिसंबर को



सुनाया जाएगा। कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जाँय को पांच साल जेल और 100,000 ड़का का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को पांच साल की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2024 में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों को दबाने की शेख हसीना

की कोशिशों के लिए उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना और हसीना को मौत की सजा सुनाई।

इस दौरान शेख हसीना और उनके परिवार के पास इन मामलों में कोई वकील नहीं था। हालांकि, उन्होंने अलग-अलग भाषणों और बयानों में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल होने से इनकार किया है।

इन सब के बीच बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के उन अनुरोधों की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी पीपुस शेख शाहजद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली को इस मामले पर ढाका से औपचारिक रूप से जानकारी मिली है।

पेपर स्प्रे फेंकने वालों को थाने में पीट रही है दिल्ली पुलिस



नई दिल्ली, एजेंसी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरिंदम सिंह चीमा की कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की अर्जी पर यह आदेश दिया। पुलिस ने सात दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल तीन दिनों की अनुमति दी। आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। कर्तव्य पथ से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान संयुक्त पुलिस अच्युत दीपक पुरोहित और डीसीपी देवेश महला महला अदालत में मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि नौ नवंबर को आरोपियों ने इंडिया गेट के पास सड़क जाम

की और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि तीन आरोपियों अश्वय, आकाश और एक अन्य से तीन कैन पेपर स्प्रे बरामद किए गए हैं। साथ ही, आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे और लाल सलाम के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए एफएएसएल भेजने की बात कही है। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। दो आरोपियों के वकील ने कहा कि उन्हें हिरासत में पीटा गया और उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। वकीलों ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग भी की।

ट्रंप का ताइवान मुद्दे पर जापान को कड़ा संदेश, ‘मत लो चीन से पंगा...स्थिति और न बिगाड़ो’!

वाशिंगटन, एजेंसी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की पीएम साने ताकाइची को चीन के साथ बढ़ते तनाव पर बड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने फोन पर ताकाइची से कहा कि ताइवान को लेकर टकराव बढ़ाने से बचें, क्योंकि यह एशिया में नई अस्थिरता को जन्म दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने ताइवान को लेकर चीन के साथ बढ़ते तनाव को संभलकर हैंडल करने की सलाह दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्योदो न्यूज के अनुसार, ट्रंप ने ताकाइची से कहा कि उनके बयान से पहले ही टोक्यो-बीजिंग रिश्ते में तनाव बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें अधिक उग्र बयानबाजी से बचना चाहिए। यह चर्चा उस समय हुई जब ताकाइची ने जापानी संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो यह जापान के लिए अस्तित्व संकट बन सकता है। चीन ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी।सूत्रों के अनुसार, ट्रंप ने ताकाइची पर दबाव नहीं डाला, लेकिन सुझाव दिया कि वे अपने बयान का टोन थोड़ा हल्का करें, क्योंकि वे चरंतू राजनीति को देखते हुए इसे पूरी तरह वापस नहीं ले सकते।।रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जापानी अधिकारियों ने ट्रंप की सलाह को इस संकेत के रूप में देखा कि वे नहीं चाहते कि ताइवान मुद्दा उनकी हालिया चीन के साथ नरमी को खराब करे-विशेष रूप से उस समय जब चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया है। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि उनकी ताकाइची से बहुत अच्छी बातचीत हुई है और वे मानते हैं कि जापान और चीन दोनों ठीक हैं। उनकी यह कॉल ताइवान पर बयान के तुरंत बाद आई थी, और उससे कुछ ही पहले वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात कर चुके थे।



शाहीन मुजम्मिल की पत्नी है, मरिजद में किया निकाह... दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के लालकिला के पास हुए बम विस्फोट की जांच में एक चौकाने वाला खुलासा सामने आया है। गिरफ्तार संदिग्ध मुजम्मिल अहमद गनई ने जांच एजेंसियों को बताया कि सहअरोपी शाहीन शाहिद उसकी पत्नी है, न कि महज प्रेमिका, जैसा पहले समझा जा रहा था। इस दावे ने न केवल मामले के मानवीय पहलू को उजागर किया है, बल्कि शाहीन द्वारा दिए गए भारी-भरकम फंडिंग के पीछे की वजह को भी



स्पष्ट करने का प्रयास किया है। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि सितंबर

2023 में अल-फलाह विश्वविद्यालय के निकट एक मस्जिद में शाहीन के साथ उसका निकाह हुआ था। इस निकाह में

शरिया कानून के अनुसार महर की राशि 5,000 से 6,000 रुपये निर्धारित की गई थी। इस वैवाहिक संबंध का दावा मामले के उस पहलू को समझाने में महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें शाहीन ने मुजम्मिल को भारी मात्रा में धन उपलब्ध कराया। जांच के अनुसार, शाहीन ने वर्ष 2023 में मुजम्मिल को हथियार खरीदने के लिए करीब 6.5 लाख रुपये दिए, जबकि 2024 में उमर को फोर्ड इकोस्पोर्ट कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपये का लोन दिया।

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष आवास योजना लेकर आ रहा है, जिसका नाम है कर्मयोगी आवास योजना। यह योजना के तहत नरेला में करीब 3,500 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना न केवल किकायती आवास प्रदान करेगी, बल्कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में सुनियोजित और सुरक्षित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण भी सुनिश्चित करेगी। पंजीकरण प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है।

यह योजना विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अस्पतालों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। केवल इन क्षेत्रों में कार्यरत योग्य कर्मचारी ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

डीडीएजल्द लॉन्च करेगी कर्मयोगी आवास योजना; जाने खासियत



योजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत और व्यवस्थित आवासीय समुदाय बनाना है, जहां वे एक ही परिसर में रह सकें। योजना को और आकर्षक बनाने के लिए फ्लैट्स की कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फ्लैट्स नरेला के सेक्टर ए1 से ए4 के तीन पॉकेट्स में स्थित होंगे और ये सभी

गेटेड सोसाइटियों के रूप में विकसित किए गए हैं। नरेला, जो दिल्ली मास्टर प्लान में भविष्य के शहरी विस्तार का प्रमुख केंद्र माना गया है, इस योजना के लिए एक आदर्श स्थान है। योजना तीन चरणों में फ्लैट्स की पेशकश करेगी। इनमें उच्च आय वर्ग (एचआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास शामिल हैं इन सभी फ्लैट्स का निर्माण हाल ही में पूरा हो चुका है। डीडीए वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया, ब्रोशर और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है। यह योजना नरेला के समग्र विकास का हिस्सा है। यहां मेट्रो और बस सेवाओं के माध्यम से राजधानी के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है।